Statement

Sl. No.	Name of the Project/ District/State	Capacity (MW)
1.	Visakhapatnam TPS, Visakhapatnam, Andhra Pradesh	1040
2.	Neyyeli (Zero Unit), South Arcot, Tamil Nadu	250
3.	Mangalore TPS, South Canara, Karnataka	1000
4.	Bhadravati TPS, Chandrapur, Maharashtra	1072
5.	Ib Valley TPS, Unit 3 & 4, Jharsuguda, Orissa	420
6.	Jegurupadu CCGT East (Godavari, Andhra Pradesh)	216
7.	Godavari CCGT, East Godavari, Andhra Pradesh	208
8.	Dabhol CCGT, Phase-I, Ratnagiri, Maharashtra	740

टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

2042. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन जिलों में पुर्नवासित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्थापन में भारी धांधली हुई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) टिहरी के भू-भवन संपत्ति धारकों और वहां के मूल निलासियों के अलावा कितने लोगों ने विस्थापन का फायदा उठाया; और

(घ) क्या सरकार के हनुमंत राव समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर उनके पुर्नवास हेतु कोई एक मुश्त (पैकेज) योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) टिहरी बांध के कारण टिहरी शहर के कुल 5291 शहरी आवासीय परिवार तथा टिहरी गढ़वाल में गांवों में रह रहे 5012 ग्रामीण परिवार विस्थापित होंगे। पुर्नवास कार्यक्रम के चरण-I के तहत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को टिहरी गढ़वाल देहरादून तथा हरिद्वार जिलों में स्थापित किया जाएगा।

(ख) विस्थापन में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरा की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) टिहरी हाइड्रो डेवलपमैंट कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुर्नवास नीति के अनुसार, ऐसे परिवार जिसकी भूमि / घरों की क्षति हुई है तथा 6 जून, 1985 को टिहरी शहर में रह रहे लोगों के साथ किराएदारों को भी पुनर्वास लाभ दिए जा रहे हैं।

(घ) टिहरी जल विद्युत परियोजना के पुनर्वास तथा पर्यावरणीय पहलुओं की जांच हेतु 17 दिसम्बर, 1996 को स्थापित हनुमंत राव समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। इस समिति का कार्यकाल अब 15 मई, 1997 तक बढ़ा दिया गया है।

अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जिलों के गांवों का विद्युतीकरण

2043. **श्री मनोहरकान्त ध्यानी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जिलों में ऐसे कितने गांव हैं जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) उन गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या छोटे-छोटे गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक या अन्य किसी अभिकरण से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अल्मोड़ा, पौड़ी तथा चमोली जिलों के क्रमशः 521, 1064 तथा 371 बसे हुए गांव हैं जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

(ख) वर्ष 1966-97 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अल्मोड़ा, पौड़ी तथा चमोली जिलों में क्रमशः 47, 53 तथा 27 बसे हुए गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया है।

(ग) जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सूचना के अनुसार जिला सलाहकार समिति द्वारा चुने हुए गांवों के आकार पर ध्यान न देते हुए इन्हें विद्युतीकरण के लिए हाथ में लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Additional Capacity to Meet Energy Requirement

2044. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Working Group on Power has projected 55761 MWs additional capacity to get over the prevailing energy shortages;

(b) whether this additional capacity for power is likely to be the target in the 9th Five Year Plan;

(c) what is the estimated outlay requirement for power sector in that plan;

(d) whether target set for the 8th Five Year Plan has been achieved or is likely to be achieved;

(e) if not, the details in this regard; and

(f) whether the Ninth Five Year Plan for power is being prepared by the Working Group on the basis of the internal resources; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) and (f) The Working Group on Power for 9th Plan has recommended a capacity addition of 57735MW during 9th Plan to meet the power requirements projected by 15th Electric Power Survey Committee.The targets for the Ninth Plan and outlay are still under finalisation by the Planning Commission.

(d) and (e) As against a capacity addition programme of 30537.7 MW during the Eighth Plan, the achievement is expected to be around 17668 MW. The main reasons for shortfall have been paucity of resources with the States, rehabilitation & resettlements issues, law and order etc.

राज्य बिजली बोर्डों के घाटे

2045. **श्री गोपाल सिंह सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 में 31 दिसम्बर, तक गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को, वार्षिक रिपोर्टों और केन्द्रीय सरकार के आंकलन के अनुसार, बिजली के उत्पादन एवं वितरण में तुलनात्मक दृष्टि के लोगों से कितना-कितना घाटा या लाभ हुआ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में लगातार आई गिरावट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) कुछ रा०बि०बो० के लेखों का निर्धारण न होने की वजह से, वर्ष 1995-96 हेतु सभी रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी उपलब्ध नहीं है। तथापि, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड सहित रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को गणना में लेकर, जैसा कि वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 हेतु लेखों में प्रदान किया गया है, क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों / विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति तीव्रता से गिर रही है तथा विद्युत क्षेत्र के भावी विकास को व्यवहार्य राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार के बगैर नहीं बनाए रखा जा सकता।